

यू.पी.एस.सी

मुख्य परीक्षा अध्ययन सामाग्री

सामान्य अध्ययन

प्रश्नपत्र – 3

(शासन व्यवस्था, शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय
तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध)



सत्यमेव जयते



Published By

Develop India Group

<http://www.developindiagroup.co.in/>

Published by

Develop India Media Group

Allahabad

Mobile : 08756987953

email : subscriptiondevelopindia@gmail.com

Edition : 2018

Develop India Group Aims

We conduct *Study Material Programme, All India Correspondence Courses, Test Series Programmes* for various competitive exams with our expert faculties. Our aim to provide quality of materials to you in your remote areas.

You can find here

Develop India weekly Newspaper, MINERVA Hindi Monthly Magazine, Books for all competitive Exams, Notes & Study Materials for all competitive exams.

If you want to buy any kind of entrance exam forms/vacancy/previous year question papers, you can contact us.

Copywrite

All matter compile in this notes from various sources believed to be reliable. We published very carefully to this matter, its authors can not take guarantee the occuracy or completeness of any information published herein and neither **Develop India Media Group** nor its authors shall be responsible for any errors, omissions or damage arising out of use of this information.

No part of this notes may be reproduce or transemitted without the written permission of the publisher.

All right reserved.

Note : All disputes with respect to this publication shall be subject to jurisdiction of the courts, tribunals and forums of Allahabad, India.

Contact us

CORPORATE OFFICE

Develop India Media Group

Allahabad

Mobile : 08756987953

emails : subscriptiondevelopindia@gmail.com,

developindiamediagroup@gmail.com

अनुक्रमिका

● भारतीय संविधान ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं, संशोधन, महत्त्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी संरचना	5	● संसदीय विशेषाधिकार	29
● भारतीय संविधान ऐतिहासिक आधार	5	● सामूहिक विशेषाधिकार	29
● रेग्युलेटिंग ऐक्ट, 1773	5	● व्यक्तिगत विशेषाधिकार	30
● पिट्स इंडिया ऐक्ट, 1784	5	● वित्तीय प्रावधान	30
● 1813 का चार्टर ऐक्ट	5	● बजट का अधिनियमन	30
● 1833 का चार्टर ऐक्ट	5	● संसदीय समितियां	31
● 1853 का चार्टर ऐक्ट	5	● राज्य कार्यपालिका	32
● 1858 का भारत सरकार अधिनियम	5	● राज्यपाल	32
● 1861 का भारतीय परिषद् अधिनियम	6	● राज्यपाल की भूमिका एवं स्थिति	33
● 1892 का भारतीय परिषद् अधिनियम	6	● राष्ट्रपति और राज्यपाल का तुलनात्मक अध्ययन	34
● भारतीय परिषद् अधिनियम, 1909 (मार्ले-मिंटो सुधार)	6	● मुख्यमंत्री	34
● भारत सरकार अधिनियम, 1919 (माण्टेग्यू एवं चेम्सफोर्ड सुधार)	6	● मंत्रिपरिषद्	34
● नेहरू रिपोर्ट	6	● राज्य का महाधिवक्ता (एडवोकेट जनरल)	34
● भारतीय शासन अधिनियम, 1935	6	● राज्य विधान मंडल	35
● भारत स्वतंत्रता अधिनियम, 1947	7	● विधानसभा	35
● भारतीय संविधान की विशेषताएं	8	● विधान परिषद्	35
● उद्देशिका	9	● मुख्य सचिव	35
● उद्देशिका की वैधानिक स्थिति	11	● मुख्य सचिव की भूमिका एवं कार्य	36
● उद्देशिका का दर्शन और महत्त्व	11	● अवांश्टि कार्य	36
● राज्यों का पुनर्गठन	11	● राज्य सचिवालय	36
● धर आयोग	11	● सचिवालय के कार्य एवं भूमिका	36
● जेवीपी समिति	11	● निदेशालय	37
● फजल अली आयोग	11	● सचिवालय-निदेशालय सम्बंध	38
● छोटे बनाम बड़े राज्य	12	● कार्यपालिका की संरचना, संगठन और कार्य	38
● नागरिकता	12	● भारत का राष्ट्रपति	38
● नागरिकता प्राप्ति के तरीके	12	● निर्वाचन	39
● नागरिकता की समाप्ति	13	● संवैधानिक स्थिति	39
● मूल अधिकार	13	● राष्ट्रपति की शक्तियां	39
● नीति निर्देशक तत्व	17	● कार्यपालिका शक्तियां	39
● नीति निर्देशक सिद्धांतों और मूलाधिकारों का सम्बंध	18	● विधायी शक्तियां	40
● मूल कर्तव्य	18	● वीटो शक्ति	40
● संविधान संशोधन	18	● वित्तीय शक्तियां	40
● संघ एवं राज्यों के कार्य तथा उत्तरदायित्व, संघीय ढांचे से संबंधित विषय एवं चुनौतियां	19	● न्यायिक शक्तियां	40
● संघ-राज्य क्षेत्र	19	● कूटनीतिक शक्तियां	41
● स्थानीय स्तर पर शक्तियां एवं वित्त का हस्तांतरण और उसकी चुनौतियां	23	● आपातकालीन शक्तियां	41
● पंचायती राज व्यवस्था	23	● राष्ट्रीय आपात	41
● 73वें संविधान संशोधन की विशेषताएं	23	● राष्ट्रपति शासन	41
● पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तिकरण हेतु सुझाव	24	● वित्तीय आपात	42
● नगरीय स्थानीय शासन/ नगरपालिकाएं	24	● राष्ट्रपति की भूमिका	42
● 74वें संविधान संशोधन की विशेषताएं एवं महत्त्व	24	● प्रधानमंत्री	43
● विभिन्न घटकों के बीच शक्तियों का पृथक्करण, विवाद निवारण तंत्र तथा संस्थान	25	● राष्ट्रपति-प्रधानमंत्री सम्बंध	44
● सरकारिया आयोग	27	● कैबिनेट (मंत्रिमंडल)	44
● भारतीय संवैधानिक योजना की अन्य देशों के साथ तुलना	27	● मंत्रिमंडल समितियां	44
● संविधान के स्रोत	27	● महान्यायवादी (अटार्नी जनरल)	45
● संसद और राज्य विधायिका, संरचना, कार्य, कार्य-संचालन, शक्तियां एवं विशेषाधिकार और इनसे उत्पन्न होने वाले विषय	28	● न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्य	45
● संसद	28	● उच्चतम न्यायालय	45
● राज्यसभा	28	● न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया	45
● लोकसभा	29	● उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार	45
● दोनों सदनों की संयुक्त बैठक	29	● उच्चतम न्यायालय की भूमिका	46
		● लोकहित याचिका	46
		● न्यायिक सक्रियता	46
		● उच्च न्यायालय	46
		● अधीनस्थ न्यायालय	47

● सरकार के मंत्रालय और विभाग	47	● गुट निरपेक्षता	98
● प्रभाव समूह	49	● राष्ट्रमंडल	100
● औपचारिक और अनौपचारिक संघ तथा शासन प्रणाली में उनकी भूमिका	49	● विकसित तथा विकासशील देशों की नीतियों तथा राजनीति का भारत पर प्रभाव	101
● जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं	49	● महत्त्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, संस्थाएं और मंच – उनकी संरचना, अधिदेश	103
● विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति और विभिन्न संवैधानिक निकायों की शक्तियां, कार्य और उत्तरदायित्व	50	● संयुक्त राष्ट्र संघ	103
● सांविधिक, विनियामक और विभिन्न अर्ध-न्यायिक निकाय	60	● संयुक्त राष्ट्र संघ तथा मानवाधिकार	107
● निर्वाचन आयोग	60	● अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण	109
● परिसीमन आयोग	61	● अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन	110
● नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक	61	● विश्व स्वास्थ्य संगठन	110
● वित्त आयोग	61	● संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन	111
● योजना आयोग	62	● खाद्य एवं कृषि संगठन	112
● राष्ट्रीय विकास परिषद	62	● अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष	112
● नियामक	63	● अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक / विश्व बैंक	112
● न्यायाधिकरण	64	● विश्व बैंक की अन्य संस्थाएं	113
● प्रशासनिक न्यायाधिकरण	64	● विश्व बौद्धिक सम्पदा संगठन	113
● हित-समूह	66	● सार्वभौम डाक संघ	114
● स्वैच्छिक संगठन	66	● विश्व व्यापार संगठन	114
● योजना आयोग	67	● अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ	114
● आर्थिक विकास तथा सामाजिक न्याय हेतु विकेंद्रीकरण आयोजना	71	● विश्व पर्यटन संगठन	115
● घरेलू हिंसा अधिनियम	72	● अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन	115
● राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग	73	● विश्व मौसम विज्ञान संगठन	115
● स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित विषय	73	● अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक व्यापार संगठन	115
● गरीबी और भूख से संबंधित विषय	74	● संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन	116
● गरीबी निवारण कार्यक्रम	74	● संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम	116
● शासन व्यवस्था, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्त्वपूर्ण पक्ष	75	● संयुक्त राष्ट्र बाल कोष	116
● लोकपाल	75	● संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम	117
● लोकायुक्त	75	● संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन	117
● सुशासन के तत्व	76	● अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय	117
● भारत के संदर्भ में सुशासन	76	● मानव अधिकारों के लिए सं.रा. हाई कमिश्नर का कार्यालय	117
● उदारीकरण, निजीकरण तथा वैश्वीकरण की चुनौतियां	77	● यूरोपीय संघ	118
● ई-गवर्नेंस अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएं, सीमाएं और संभावनाएं	78	● गुप-8	119
● नागरिक चार्टर, पारदर्शिता और जवाबदेही और संस्थागत तथा अन्य संपादन	81	● अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं	119
● नागरिक चार्टर	81	● एशियाई विकास बैंक	119
● केंद्रीय सतर्कता आयोग	81	● अफ्रीकी विकास बैंक	119
● केंद्रीय जांच ब्यूरो	81	● गुप-10	119
● लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका	81	● इस्लामिक विकास बैंक	119
● संवैधानिक संरक्षण	82	● अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक संगठन	119
● नई अखिल भारतीय सेवाएं	82	● आर्थिक सहयोग और विकास संगठन	119
● संघ लोक सेवा आयोग	82	● यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ	120
● भारत एवं इसके पड़ोसी देशों से संबंध	82	● दक्षिणी साझा बाजार	120
● भारत और पाकिस्तान	82	● एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग	120
● जम्मू-कश्मीर समस्या	83	● यूरोपियन आर्थिक समुदाय	120
● मैकनॉटन योजना	84	● उत्तरी अमेरिका मुक्त व्यापार समझौता	120
● डिक्सन योजना	84	● अंतर्राष्ट्रीय मंच	120
● ग्राह्य योजना	84	● पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन	120
● भारत-चीन	86	● कोलम्बो योजना	121
● भारत व चीन के बीच हुए 13 समझौते	88	● मेकांग-गंगा सहयोग	121
● 10 सूत्रीय विचारधारा	88	● गल्फ सहयोग परिषद	121
● भारत-नेपाल	88	● शंघाई सहयोग संगठन	121
● शांति तथा मैत्री पूर्ण संधि	88	● अरब लीग	121
● व्यापार वाणिज्य संधि	89	● अफ्रीकी संघ	122
● वर्तमान स्थिति	89	● अंतर्राष्ट्रीय रेडक्रास समिति	122
● भारत-बांग्लादेश	90	● उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन	122
● भारत-श्रीलंका	93	● इब्सा	123
● भारत-म्यांमार	96	● मेडिसिन्स सेन्स फ्रंटियर्स	123
● द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से संबंधित और/अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले करार	97	● एमनेस्टी इंटरनेशनल	123
● दक्षिण-पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ – आसियान	97	● इस्लामिक सम्मेलन संगठन	123
● दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन – दक्षेस	97	● ग्रीनपीस	124
		● अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन	124
		● प्रकृति के लिए विश्वव्यापी कोष	124
		● अंतर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति	124
		● विश्व सामाजिक मंच	124

शासन व्यवस्था, शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध

भारतीय संविधान ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी संरचना

भारतीय संविधान ऐतिहासिक आधार

भारतीय संविधान का निर्माण अनेक ऐतिहासिक घटनाओं पर निर्भर था। ब्रिटिश काल के दौरान विकसित लक्षणों ने संविधान निर्माण की पृष्ठभूमि निर्मित की। ये लक्षण निम्नलिखित हैं :

रेग्युलेटिंग ऐक्ट, 1773

- इस ऐक्ट के तहत संसदीय नियंत्रण का आरम्भ हुआ।
- बंगाल का गवर्नर, गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस प्रकार वारेन हेस्टिंग्स प्रथम गवर्नर जनरल बना।
- मद्रास और बम्बई प्रेसीडेंसी बंगाल के अधीन हो गईं।
- इसने भारत में केंद्रीकृत शासन प्रणाली का आरम्भ किया।
- कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय का प्रावधान किया गया। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजाह इम्पे बने।

पिट्स इंडिया ऐक्ट, 1784

- इस अधिनियम को रेग्युलेटिंग ऐक्ट की कमियों को दूर करने के लिए पारित किया गया।
- इसके द्वारा भारतीय मामलों को ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण में कर दिया गया।
- कम्पनी के शासकीय निकाय अर्थात् निदेशक मंडल के ऊपर छह सदस्यीय 'नियंत्रक मंडल' का गठन किया गया। भारत मंत्री, वित्त मंत्री, चार प्रिवी काउंसिलर सदस्यों को भारतीय मामलों का आयुक्त बनाया गया।
- पिट्स ऐक्ट की व्यवस्था 1857 तक चलती रही।

1813 का चार्टर ऐक्ट

- कम्पनी के भारत में व्यापारिक एकाधिकार (चाय को छोड़कर) को समाप्त कर दिया गया और ब्रिटिश निवासियों को भारत से व्यापार करने की छूट दी गई।
- कम्पनी की वाणिज्यिक आय को क्षेत्रीय राजस्व से पृथक कर दिया गया।
- स्थानीय स्वायत्तशासी संस्थाओं को करारोपण का अधिकार दिया गया।
- भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपये वार्षिक व्यय करने का प्रावधान किया गया।
- धर्म विभाग (एक्लीजिओस्टिकल विभाग) की स्थापना की गई। इस ऐक्ट में नीति-निदेशक तत्वों के बीज देखने को मिलते हैं।

1833 का चार्टर ऐक्ट

- ये ब्रिटिश भारत में केंद्रीयकरण की ओर अंतिम चरण माना जाता है। कम्पनी के व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया और वह प्रशासनिक संस्था की भूमिका निभाने लगी।
- बंगाल का गवर्नर भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने।
- गवर्नर जनरल के परिषद में एक चौथा सदस्य विधि सदस्य के रूप में जोड़ा गया। लॉर्ड मैकाले प्रथम विधि सदस्य बने।
- बॉम्बे, मद्रास की सरकारों को विधायी अधिकार से वंचित कर दिया गया।
- इसमें यह प्रावधान किया गया कि केवल जन्म, जाति, वर्ग, धर्म या जन्मस्थान के आधार पर किसी को किसी पद या सेवा से वंचित नहीं किया जाएगा।
- लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया और IPC, CrPC और CPC का निर्माण किया गया।
- पहली बार इस अधिनियम में भारतीय संविधान में वर्णित मूलाधिकारों के बीज देखने को मिलते हैं।

1853 का चार्टर ऐक्ट

- इस ऐक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल की कार्यपालिका एवं विधायी शक्तियां पृथक की गईं।
- भारत के लिए अलग विधान परिषद की स्थापना की गई।
- भारतीय विधान परिषद में क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया।
- विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर गवर्नर जनरल की अनुमति अनिवार्य कर दी गई तथा उसे वीटो पावर भी दी गई।
- कम्पनी के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए योग्यता प्रणाली को मान्यता दी गई।

1858 का भारत सरकार अधिनियम

- इसे 'ऐक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट फॉर इंडिया' कहा गया।
- कम्पनी का शासन समाप्त किया गया और भारतीय सत्ता ब्रिटिश ताज को दे दी गई।
- भारतीय मामलों का प्रभारी ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होता था, जिसे भारत मंत्री कहा गया। उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद बनाई गई। भारत मंत्री (सचिव) ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था।
- गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। इस प्रकार लॉर्ड कैनिंग भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय बने।

1861 का भारतीय परिषद् अधिनियम

1861 ई. में 'प्रथम भारतीय परिषद् अधिनियम' पारित किया गया। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित थीं :

- वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया।
- वायसराय की परिषद में भारतीय प्रतिनिधियों को नामित करने का अधिकार दिया गया।
- पहली बार भारतीयों को विधायी कार्यों में संलग्न किया गया।
- गवर्नर जनरल को संकटकालीन अवस्था में विधान परिषद की अनुमति के बिना ही अध्यादेश जारी करने की अनुमति दे दी गई। ये अध्यादेश अधिकाधिक 6 मास तक लागू रह सकते थे।

1892 का भारतीय परिषद अधिनियम

इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित थीं :

- इस अधिनियम ने भारत में प्रतिनिधित्व प्रणाली या प्रतिनिधि सरकार की शुरुआत की।
- वार्षिक बजट पर चर्चा करने की अनुमति दी गई।
- कुछ शर्तों के अधीन सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया।

भारतीय परिषद अधिनियम, 1909 (मार्ले-मिंटो सुधार)

- मार्ले-मिंटो सुधार का लक्ष्य 1892 के अधिनियम के दोषों को दूर करना तथा भारतीय राजनीति में बढ़ते हुए उग्रवाद तथा क्रांतिकारी राष्ट्रवाद से उत्पन्न स्थिति का सामना करना था। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित थीं :
- अप्रत्यक्ष निर्वाचन के सिद्धांत को मान्यता दी गई।
- साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की शुरुआत की गई, जिसमें मुस्लिम सम्प्रदाय के लिए अलग निर्वाचक मंडल का निर्माण किया गया।
- सार्वजनिक महत्त्व के विषय पर बहस का अधिकार दिया गया।
- परिषद के भारतीय सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया।
- इस अधिनियम के द्वारा भारत सचिव की परिषद तथा भारत के वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में सर्वप्रथम भारतीय सदस्यों को सम्मिलित किया गया। दो भारतीय के.सी. गुप्ता तथा सैय्यद हुसैन बिलग्रामी को इंग्लैंड स्थित भारत परिषद में नियुक्त किया गया।

भारत सरकार अधिनियम, 1919 (माण्टेग्यू एवं चेम्सफोर्ड सुधार)

- यह माउण्टेफोर्ड योजना पर आधारित था, जिसे 1921 से भारत में लागू किया गया।
- इस अधिनियम के द्वारा उत्तरदायी शासन की स्थापना का प्रयास किया गया।
- प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई, जिसके तहत प्रांतीय सरकार के दो भाग हो गए :
 1. आरक्षित : जिसका प्रशासन गवर्नर अपने द्वारा मनोनीत सदस्यों के माध्यम से करता था।
 2. हस्तांतरित : जिसका प्रशासन गवर्नर, विधानमंडल के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा बनी मंत्रिपरिषद की सहायता से करता था।

- स्थानीय स्वशासन प्रांतीय तथा हस्तांतरित विषय बनाया गया।
- केंद्र में द्विसदनात्मक विधानमंडल की स्थापना की गई, जिन्हें विधानसभा तथा राज्य परिषद का नाम दिया गया। केंद्रीय विधानसभा का कार्यकाल तीन वर्ष का था और ये पूरे भारत के लिए कानून बना सकती थी।
- भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की स्थापना की गई।
- वायसराय की परिषद में भारतीय सदस्यों की संख्या बढ़ाकर तीन कर दी गई।
- महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया।
- इस अधिनियम के द्वारा स्त्रियों को मताधिकार दिया गया।

नेहरू रिपोर्ट

विभिन्न राजनीतिक दलों ने साइमन आयोग का बहिष्कार किया और भारत के लिए संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। इसका प्रतिवेदन 10 अगस्त, 1928 को प्रकाशित हुआ जिसमें निम्नलिखित सिफारिशों की गईं :

- भारत के साथ अन्य उपनिवेशों की तरह ही व्यवहार किया जाए।
- भारतीयों को मूल अधिकार दिए जाने चाहिए।
- संसद में दो सदन हों – निचला सदन, जिसके सदस्य वयस्क मताधिकार द्वारा निर्वाचित हों। गवर्नर जनरल कार्यकारी परिषद की सलाह पर कार्य करे। कार्यकारी परिषद सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी हो। इसी प्रकार के उपबंध प्रांतों में लागू किए जाएं।
- निर्वाचक मंडल संयुक्त और मिश्रित हों। केंद्र में मुसलमानों के लिए स्थान आरक्षित किए जाएं। जिन प्रांतों में मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं वहां भी उनके लिए आरक्षण हो।
- जहां आरक्षण किया गया है वहां भी मुस्लिम या गैर-मुस्लिम अतिरिक्त स्थानों पर चुनाव लड़ सकेंगे।
- सिंध को अलग करके मुस्लिम बहुल प्रांत बनाया जाए।
- पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत को, प्रांत का दर्जा दिया जाए।
- स्थानों का आरक्षण 10 वर्ष के लिए हो।

भारतीय शासन अधिनियम, 1935

- भारत के लिए तैयार किए गए संवैधानिक प्रस्तावों में यह अंतिम था। यह सबसे बड़ा और जटिल दस्तावेज था। इसमें 14 भाग 321 धाराएं तथा 10 अनुसूचियां थीं। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित थीं :
- भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना का प्रावधान किया गया।
- केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना का प्रस्ताव किया गया।
- प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त किया गया।
- केंद्र एवं प्रांतों में विधायिका द्विसदनीय बनाई गई।
- केंद्रीय विधायिका का कार्यकाल पांच वर्ष और राज्य परिषद को स्थायी बनाया गया।
- प्रांतों में स्वायत्त शासन की स्थापना की गई, जिसकी कार्यपालिका शक्ति गवर्नर में निहित होती थी और वह प्रांतीय मंत्रिमंडल का प्रमुख था।
- प्रांतों में साम्प्रदायिक निर्वाचन का विस्तार हरिजनों तक किया गया।